International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 4 Ser. I || April 2019 || PP 68-71

डॉ. अंबेडकर की आर्थिक विचारधारा और भारत का उदय

प्रियंशा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
हिंदू कॉलेज मुरादाबाद

परिचय

भारत सभ्यता, शिक्षा, ज्ञान और नवाचार के अपने लंबे इतिहास के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, भारत ने अनेक जाति एवं सामाजिक विषमताओं में भी अपने लोकतंत्र को मजबूत किया और मानव विकास के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। यह मंगल पर रॉकेट लॉन्च करने वाला चौथा देश बना और सबसे बड़े वैश्विक बाजार के रूप में भी उभरा अपने कुलीन वर्ग के आकार , युवा आबादी का उच्च प्रतिशत (28%, 10-24 वर्ष की आयु) और तकनीकी रूप से सुसज्जित मानव संसाधन को देखते हुए।

आइए हम यह भी मान लें कि भारत में 132 करोड़ मैं से लगभग एक तिहाई भारतीय अभी भी अत्यधिक गरीबी में हैं, वैश्विक निरक्षर वयस्कों का 35% और बेरोजगार युवा आबादी का एक उच्च प्रतिशत विद्यमान है। केवल अमीरों के लिए चमक रहे भारत में आर्थिक असमानता विषम स्तर पर पहुंच गयी है। वैश्वीकरण के बाद की अवधि में, बाजार की ताकतें के कारण वंचित वर्ग और हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं। जातिवादी पूर्वाग्रह, धार्मिक घृणा,अस्पृश्यता, बंधुआ मजदूरी और दुखद रूप से मैला ढोने की प्रथा अभी भी कुछ हद तक विद्यमान है। राजनीति-नौकरशाही ,व्यापार-मीडिया और गैर सरकारी संगठन के गठजोड़ कानून के शासन को हाईजैक करने के लिए इतने बढ़ गए हैं कि प्रत्येक समस्या को राजनीति, धर्म और जाति के रंग में रंग कर लाभ उठाने की कोशिश होती है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और घोटाले आम हैं। ऐसे सभी मुद्दे राष्ट्र और उसके निर्णयकर्ताओं के सामने चुनौतीपूर्ण चुनौतियां हैं।

इस पृष्ठभूमि में, हम, इस पत्र में, भारतरत्न डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर राष्ट्र-निर्माता के जीवन, संघर्षों और उनके शैक्षणिक कार्यों पर मंथन करेंगे। यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित उनका लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण, शैक्षिक रुचि और अकादमिक मूल्य का है जो लंबे समय तक दरकिनार रहा। उनका अध्ययन और विश्लेषण ,आपस में जुड़े सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और जाति की गतिशीलता को समझने में मदद करेगा जो भारतीय समाज के परिवर्तन में , जैसा कि डॉ.अंबेडकर ने सोचा था, मायने रखते हैं। यह उन प्रशासनिक विफलताओं को भी उजागर करता है जो उनकी आर्थिक योजनाओं और नीतियों का पालन नहीं करने के कारण से उपजीं।

डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार और उनकी विकास की अवधारणा

डॉ. अम्बेडकर का एक युवा अर्थशास्त्री से राजनीतिक के रूप में परिवर्तन

डॉ. अम्बेडकर मौलिक रूप के एक आर्थिक सिद्धांतकार थे, जो समकालीन शोध के प्रति पूर्णतः जागरूक थे और कई विषयों पर इतनी कम उम्र में उन्होंने लिखा भी। उनके काम को विश्व के अर्थशास्त्रियों द्वारा मान्यता दी गई थी। अम्बेडकर ने एक तरफ भारत में सामाजिक-राजनीतिक ढांचे और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों और दूसरी तरफ भारत को बदलने में विकास परियोजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया। वह पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यापक रूप से सार्वजनिक वित्त, कराधान और ब्रिटिश भारत के मौद्रिक मानकों,और स्थानीय व्यापार पर आंतरिक और बाहरी दोनों करों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने भारतीय मुद्रा, उधार के तरीके, विकास रणनीति, राज्य समाजवाद और राष्ट्रीयकरण, जनसंख्या और परिवार नियोजन, महिला विकास, मानव संसाधन सहित अनेक जनसांख्यिकीय पहलू, हिंदू अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर लिखा। उनका तर्क है कि भारत में दलित, पिछड़ों की गरीबी प्राकृतिक संसाधनों के अन्याय पूर्ण और असमान वितरण के कारण है, जिनसे दलित और पिछड़ों को वंचित रखा गया है। अमीर उच्च वर्ग के लिए स्थिति अलग है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति और शिक्षा के पक्ष में तर्क दिए। उनके अनुसार मौजूदा आर्थिक प्रणाली शोषण और असमानताओं को बढ़ावा देती है और कायम रखती है। डॉ. अम्बेडकर ने सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और कागज के सीमित और आर्थिक उपयोग पर जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि अर्थशास्त्र का अच्छी तरह से शोध किया गया अध्ययन सामाजिक नीति के निष्कर्षों के लिए आवश्यक है। जैसा की उनके आर्थिक लेखों में दिखता है।

डां. अंबेडकर द्वारा जीवन के शुरुआती 32- 33 वर्षों तक किया गया शैक्षणिक एवं पेशेवर लेखन अर्थशास्त्र से संबंधित था। उनकी मास्टर डिग्री थीसिस, प्राचीन भारतीय वाणिज्य (1915) और; भारत का राष्ट्रीय लाभांश (1916); ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त पर शोध कार्य (1915), भारत में छोटी जोत और उनकी उपचार (1918); ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (1925); रुपये की समस्या (1923) बयानों के अलावा, साक्ष्य, 13 समीक्षाएं जो आरबीआई की स्थापना के लिए नींव बने। जेंडर सशक्तिकरण, कार्य की स्थिति आदि, समकालीन संदर्भ में एक नई गंभीर समीक्षा के पात्र हैं। इतनी कम उम्र में उनकी अकादमिक उपलब्धियां विश्व के अनेक देशों से उन्हें आमंत्रित कर रही थी, लेकिन उन्होंने स्वदेश आकर देश की सेवा करना पसंद किया। डॉ. अंबेडकर ने इतना कुछ अर्थशास्त्र में अध्ययन और लेखन के उपरांत राजनीति में जाने का निर्णय किया और अपने राजनीतिक जीवन को सामाजिक सक्रियता और मीडिया से जोड़ा।

उन्होंने शायद महसूस किया कि, यह अंततः राजनीतिक शक्ति ही है जो लोगों के भाग्य और उनकी सामाजिक प्रगति को निर्धारित करती है। यही वास्तव में उनके जीवन का लक्ष्य और जुनून था।

सुशासन हेतु सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना आवश्यक है:

डॉ. अम्बेडकर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और बड़े करीने और निष्पक्ष रुप से सार्वजनिक वित्त में हो रहे सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सामने लाये। सामूहिक जिम्मेदारी और सरकार की निष्पक्षता पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा,""यह स्पष्ट है कि अच्छा प्रशासन अच्छे वित्त पर निर्भर करता है, क्योंकि वित्त पूरी प्रशासनिक मशीन का ईंधन है। किसी भी योजना अथवा बदलाव के लिए किसी भी नई प्रणाली के प्रशासनिक शुरुआत हेतु उसके आर्थिक पहलू का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि यदि प्रांतों की वित्तीय स्थिरता निर्विवाद हो, तो यह अंततः भारत सरकार को ही ख़तरे में डाल देता है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रांतीय घाटों को सार्वजनिक रूप से या केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लेकर पूरा किया जाना उचित नहीं है। वे आगे जोड़ते हैं ,"प्रशासन को सुचारू रूप से काम करना है, तो "इसे निष्पक्षता के सिद्धांत और सरकारी कार्य और उसके निष्पादन में प्रशासकों की सामूहिक जिम्मेदारी को पहचानना होगा ।"

भारतीय मुद्रा के प्रबंधन के लिए क्रय शक्ति को स्थिर करने की आवश्यकता:

डॉ. अम्बेडकर के डिलीट के लघु शोध की एक त्वरित समीक्षा 'रुपये की समस्या' दर्शाता है कि उन्होंने मौद्रिक और विनिमय मानकों जिसमें भारत में स्थापित स्वर्ण विनिमय और स्वर्ण विनिमय मानक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1800-1893) का पता लगाया। महंगाई, व्यापार घाटा, खर्च आदि से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की । प्रोफेसर कीन्स के भारतीय मुद्रा को फिर से तैयार करने के बारे में कई प्रस्ताव से अम्बेडकर सहमत नहीं थे। उन्होंन तर्क दिया कि फाउलर समिति की सिफारिशों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने जोर दिया कि मूलभूत तथ्य जिसे समझने और उजागर करने की आवश्यकता है, वह यह है कि रुपये की स्थिरता तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक कि "सामान्य क्रय शक्ति" स्थिर न हो। उन्होंने सिफारिश की, कि रुपये को स्वर्ण में प्रभावी परिवर्तनीयता प्रदान की जाए । लेकिन जोड़ते है, जारी करने की एक निश्चित सीमा के साथ"एक अपरिवर्तनीय रुपया होना एक बेहतर तरीका होगा।" अपनी पुस्तक"रुपये की समस्या" के पहले संस्करण की प्रस्तावना में अम्बेडकर लिखते हैं, "भारतीय मुद्रा पर मौजूदा ग्रंथ उन परिस्थितियों की विवेचना नहीं करते हैं जिसके कारण से 1893 के सुधार हुए। मुझे लगता है कि मुद्रा संकट के मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों को समझने के लिए प्रारंभिक इतिहास आलोचनात्मक अध्ययन काफी आवश्यक है … । इसी को ध्यान में रखते हुए, मैंने भारतीय मुद्रा की सबसे उपेक्षित अवधि 1800 से 1893 का अध्ययन किया।" अन्य लेखकों ने अचानक विनिमय मानक की कहानी शुरू की, इतना ही नहीं उन्होंने इस धारणा को भी लोकप्रिय बनाया कि मूल रूप से मानक के रूप में विनिमय मानक भारत सरकार द्वारा विचार किया गया। "मुझे लगता है कि यह एक घोर त्रुटि है।"

औद्योगिकरण और कृषि सुधार : प्रच्छन्न बेरोजगारी और बेहतर भूमि उपयोग के लिए आवश्यक है:

जोतों के आकार और उत्पादकता संबंध का विश्लेषण करते हुए डॉ. अम्बेडकर अन्य देशों के अध्ययनों की समीक्षा करते हैं, और सर हेनरी कॉटन को उद्धृत करते हैं: "भारत में बहुत अधिक कृषि का खतरा है"। उन्होंने एक महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डाला जो बाद के वर्षों में और आज भी भारत के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने कहा, "एक बड़ी कृषि आबादी वास्तविक खेती में भूमि के निम्नतम अनुपात के साथ का अर्थ है कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा फालतू और बेकार है। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी उद्योग के माध्यम से समेकित और बढ़ी हुई कृषि जोतें बेकारश्रम की समस्या को और बढ़ाएंगी। अतः लोगों की निर्भरता भूमि पर कम करने के लिए भारत का औद्योगिकरण ही "भारत की कृषि समस्याओं के लिए सबसे सुगम उपाय है" और भारत की "दोषपूर्ण राजनीतिक अर्थव्यवस्था" को देखते हुए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने के लिए भी। ग्रामीण गरीब, खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर (जिन्हें 'खोत' कहा जाता था) और 'महारवतन' एक विशेष समुदाय की एक सेवा है जिसे किसी भी समय, दिन या रात में लेने के लिए मजबूर किया जाता है के मामले को उठाने के बारे में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अमूल्य है। इससे बहुत पहले की, आधुनिक विकास सिद्धांतकारों ने कृषि विकास में उद्योग की भूमिका और प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्परोजगार की धारणा के बारे में बात की, उन्होंने बहुत पहले उद्योग-कृषि संबंधों के बारे में तर्क दिया था।

डॉ. अंबेडकर पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपखंडन की समस्या का परीक्षण किया और आर्थिक जोतों को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया:

कृषि सुधारों के क्रम में उन्होंने समेकन के मुद्दे की आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए पाया कि संपत्ति विरासत और जनसंख्या वृद्धि कृषि समस्याओं का मुख्य स्रोत है। वे आगे विवेचना करते हुए कहते हैं,"... अगर यह कहा जाए कि भारतीय कृषि छोटी और बिखरी हुई जोतों से ग्रस्त है तो हमें न केवल इन्हें समेकित करना चाहिए, बल्कि उनका विस्तार भी करना चाहिए। यह ध्यान रहना चाहिए कि चकबंदी द्वारा छोटी जोतों की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। लेकिन छोटी जोतों की बुराइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि चकबंदी द्वारा इन्हें बड़ी आर्थिक जोतों में बदला जाये।" प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेवांस के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इस तथ्य की आलोचना की है, कि प्रत्येक बड़ी जोत आर्थिक जोत होती है। वह प्रोफेसर जीवांस कि उस परिभाषा का भी खंडन करते हैं जो आर्थिक जोत को उपभोग के आधार पर परिभाषित करती है और दृढ़ता के साथ तर्क देते हुए कहा है कि उत्पादन को इसका आधार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक कृषि की अवधारणा का सुझाव संविधान सभा को दिया था लेकिन वर्चस्व वाले ग्रामीण जमींदार अभिजात वर्ग के विरोध के कारण और भूमि से जुड़ी जातियों के कारण इसे नकार दिया गया।

सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक ताकतें और नैतिक मूल्य विकास के लिए आलोचनात्मक हैं:

डॉ. अंबेडकर एक दूर द्रष्टा थे, उनकी सामाजिक- आर्थिक गठजोड़ जिसमें जातिवाद और राजनीतिक कारण भी शामिल हैं, की गतिशीलता के गहरे ज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने अनुसूचित जाति द्वारा, सार्वभौमिक वयस्कों के अधिकारों के माध्यम से शिक्षा, भूमि सुधार और

राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखा, और माना कि इसके द्वारा लोगों को स्वतंत्रता और बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन वह यहां पर ही नहीं रुके और भारतीय नेतृत्व को याद दिलाते रहे कि भारत को जातिवाद और समुदायवाद से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत काम करना है जिससे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व प्राप्त कर सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए एक स्वस्थ भारतीय समाज का निर्माण किया जा सके। वे इस बात को लेकर बहुत ही मुखर थे की संपत्ति के बराबर बंटवारे संबंधी सुधार को किसी भी सुधार से पहले किया जाना चाहिए और यह की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य भी मनुष्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक उद्देश्य। उन्होंने भारतीय नेतृत्व के आगे बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़े किए: क्या यह सरकार महसूस नहीं करती है कि जमींदार जनता का शोषण करते हैं? क्या भारत की सरकार यह नहीं महसूस करती है कि पूंजीवादी, मजदूरों को एक सम्मानजनक वेतन और रहने की स्थिति नहीं प्रदान करते हैं? उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि राजनीतिक नेतृत्व मौजूदा सामाजिक और आर्थिक जीवन के ताने-बाने में दखलअंदाजी या सुधार करने से डर रहा था क्योंकि इससे सामाजिक प्रतिरोध उत्पन्न होने का खतरा था।

डॉ. अंबेडकर एक दूरदर्शी जनवादी अर्थशास्त्री थे:

राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान व्यापक, अंतर्दृष्टिपूर्ण और भारत के संविधान के निर्माण से परे बहुत कुछ है। राज्य समाजवाद की उनकी योजना यद्यपि स्वीकार नहीं की गई वाकई रिफ्लेशनरी थी। उन्होंने देश की पूरी आर्थिक संरचना को संविधान के कानून के अंतर्गत लाने की बात कही, ना कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत। उनका पूरी तरह मानना था कि इसके बिना 'एक व्यक्ति एक मत' को 'एक व्यक्ति एक मूल्य' में नहीं बदला जा सकता है। उनकी भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की आलोचना अकादमीय रूप से काफी सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। कई विद्वानों ने यह सामने लाया है कि अंबेडकर ने बहुत ही गहराई और तीव्रता के साथ गांधीजी के अस्पृश्यता को मिटाने के ऐतिहासिक प्रयास को बड़े स्तर पर तीव्रता प्रदान की, क्योंकि इससे सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अपनी योग्यता और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले डॉ. अंबेडकर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम कैबिनेट में कानून मंत्री का पोर्टफोलियो देने के लिए आमंत्रित किया जिससे कि बहुत ही मुश्किल से हासिल की गई स्वतंत्रता को और सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रकार, वह कानून मंत्री के पद तक पहुंचे, और उन्हें 'मॉर्डेन मनु' के रूप में जाना जाने लगा। अपने श्रम और महिला अधिकारों के प्रति वास्तविक योगदान के लिए वे मानवीय सम्मान के अग्रदूत बने। उन्होंने प्रतिदिन काम के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने के संघर्ष का नेतृत्व किया , उन्होंने 1916 में महिला सशक्तिकरण पर लिखा, और भारत के प्रथम कानून मंत्री होने के नाते अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने महिलाओं को विरासत और संपत्ति का अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल को पेश किया। उन्हें सेंट्रल बैंक, नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड; रोजगार कार्यालय; केंद्रीय जल परियोजना और नीति और नेविगेशन सिस्टम जैसे कई शीर्ष स्तर के संस्थानों की स्थापना का श्रेय जाता है। पृष्ठभूमि में उनका काम इन सभी संस्थानों और परियोजनाएं के लिए न केवल प्रकृति में मौलिक है बल्कि महत्वपूर्ण रूप से अग्रणी हैं।

निष्कर्ष:

डॉ. अंबेडकर को बहुत आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वह एक महान विचारक, एक उत्साही पाठक-जो सदा जरूरतों के ऊपर किताबों को तरजीह देते थे, एक दूरदर्शी विद्वान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक, वे दलित वर्ग के सम्मान और अधिकारों के अग्रदूत थे, एक उल्लेखनीय नेता और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसे भारत के औपनिवेशिक इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रथाओं का गहन ज्ञान था। स्कूली शिक्षा हासिल करने के लिए अपने संघर्ष और अपने शिक्षकों की प्रेरणा को जीवित रखते हुए वैश्विक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक और उसे हासिल करना तथा उनका अकादमिक योगदान, ना सिर्फ हमारे छात्रों, बल्कि शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए भी महान सबक है। उनके विशाल ज्ञान के साथ-साथ उनका विश्लेषणात्मक दिमाग अपने तर्क गढ़ने, और अग्रणी देशों के संविधानों की उनकी समझ और ऐतिहासिक सोच के प्रति उनकी उत्सुकता उन्हें 'भारत के संविधान' जैसे अद्भुत दस्तावेज की रचना करने में मदद की, जिससे उन्हें "संविधान के जनक" की उपाधि दी गई। अर्थशास्त्र उनका पहला प्यार था(ऐसा महान अर्थशास्त्री सी.रंगराजन ने टिप्पणी की थी), डॉ अम्बेडकर ने लगातार कड़ी मेहनत की और और एक सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक संरचनाओं, जो मानव क्षमता के पूर्ण विकास की अनुमति देती है,और हमारे सभी नागरिकों के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करती है, की नींव रखने के लिए खुद को समर्पित किया। उनका मानना था कि रचनात्मक और प्रासंगिक नीतिगत निष्कर्षों के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है।

मौद्रिक अर्थशास्त्र, प्रांतीय और सार्वजनिक वित्त, संघीय ढांचे और कृषि अर्थशास्त्र पर उनके लेखन तथा कट्टरपंथी, सामाजिक-आर्थिक सुधारो पर उनके विचार और गुणवत्तापूर्ण राजनीतिक नेतृत्व को विकास के परिपेक्ष में रखना न केवल उनके दूरदर्शी और अग्रणी कार्य हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिकता और मौलिकता में अद्वितीय हैं। लेकिन भारतीय आर्थिक विचार में काफी समय तक इसकी अनदेखी की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि, अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान जैसे, कानूनी सिद्धांत और व्यवहार, सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान जिससे उन्होंने भारत के संविधान के वास्तुकार होने की उपाधि अर्जित की, अर्थशास्त्र में उनके लेखन पर भारी पड़ गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उन्हें सिर्फ दलित नेता के रूप में जानते हैं जबकि वह एक महान राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने दूरदर्शिता के साथ बड़ी बुद्धिमानी और समझदारी से भारत के संविधान सहित संस्थागत ढांचों का निर्माण किया। जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पथ प्रदर्शित किया।

उनके आर्थिक विचार हालांकि बिखरे हुए हैं, उन्हें नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि संविधान लागू होने के सात दशक बाद भी , उनके द्वारा 'भारत' के बारे में देखा गया सपना अधूरा है और उनके दिल के करीब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जुड़े मुद्दे अनसुलझे हैं। अतः आर्थिक सोच की वर्तमान गुणवत्ता को समृद्ध करने और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अवयवों के गुणात्मक ज्ञान द्वारा शासन और नीति निर्माण में सुधार लाते हुए देश में परिवर्तन लाया जा सके।

References:

- ***Ambirajan S., op. cit., P.***
- ***Govt. of Maharashtra (1989); op. cit., p. 327***
- ***Ibid. p. 328***
- ***Ibid.***
- ***Ibid., p. 453***
- ***Guru, Gopal (2017): "Ethics in Ambedkar's Critique of Gandhi", EPW April 15 (Vol. LII, NO. IS) p. 100***
- ***Venketaraman, R (1990) "Message" in Sudarshan Aggarwal (ed.). p. vii.***
- ***खेती के लिए भूखंड***
- डॉ कटवाल रघुनाथ सिंह, बाबासाहेब अंबेडकरके चुने हुए व्याख्यान, 2012 प्रथम संस्करण, तनिष्क पब्लिशर्स।
- मून वसंत-- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रीय जीवन चरित, प्रथम संस्करण 1991 ,नेशनल बुक ट्रस्ट ,इंडिया